बजट भाषण

2018–2019

[भाग—क]

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं लगातार चौथी बार इस सम्मानित सदन में बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. अध्यक्ष जी, मैं 2018—19 के लिए सरकार के कार्यक्रमों की रूप—रेखा प्रस्तुत करने से पहले गर्व के साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि सरकार ने शासन प्रणाली में सुधार और जन—सेवाओं के पारदर्शी तथा कारगर वितरण के ज़रिए दिल्ली के लोगों के सपने और आकांक्षाएं पूरी करने के लिए अथक परिश्रम किया है। इसे संभव बनाने में शासन के सभी घटकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और एकजुट प्रयासों का योगदान रहा है। मैं इसके लिए सभी संबद्ध पक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ।

3. अध्यक्ष जी, मैं अपने वक्तव्य में सम्मानित सदन के समक्ष सरकार की पिछले तीन वर्षो की कुछ उपलब्धियों का भी जिक्र करूंगा। आगामी वित वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट योजनाओं का भी खाका पेश करूंगा। साथ ही दिल्ली के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से संबंधित कुछ तथ्य भी सदन के समक्ष रखूंगा लेकिन इसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण संदर्भ यहां सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में रखना चाहता हूं। बजट पर आने से पहले यह जरूरी है कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार किस इकोनोमिक विजन को सामने रख कर यह बजट पेश कर रही है।

आर्थिक दृष्टिकोण

4. हमारी सरकार 3 साल से दिल्ली के आर्थिक विकास पर काम कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, न्यूनतम मजदूरी, स्किल आदि विषयों के ऐसे बुनियादी पक्ष पर काम किया है, जो आमतौर पर नजर और नजरिये से बाहर रहता था। हमारे सामने कई बार यह सवाल रखा जाता है कि हमारी सरकार की आर्थिक नीति क्या है। हमारा लोंग–टर्म–इकोनोमिक–विजन क्या है? अगर मैं 3 साल की अपनी आर्थिक गतिविधियों और इससे निकल रहे दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य को एक शब्द में कहना चाहूं तो वह है – ट्रिकल–अप इकोनोमिकस। थोडी सी रोशनी मैं इस पर डालूंगा कि इससे मेरा आशय क्या है और यह देश और दिल्ली के मोजूदा आर्थिक परिदृश्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

5. सामान्यतयः हमारे देश में इकोनोमी को लेकर हमारा नजरिया ट्रिकल–डाउन का रहा है। यानि बड़े–बड़े चंद औद्योगिक घरानों और विदेशी निवेशकों को भारी भरकम टैक्स ब्रेक, सब्सिडीज, इन्ट्रेस्ट–फ्री लोन देकर उनकी मदद करना और यह अपेक्षा रखना कि इससे सब लोगों को फायदा मिलेगा। यह एक अच्छा नजरिया है लेकिन इसके फायदे आम आदमी तक पहुचने की एक सीमा है। 90 के दशक से लेकर अब तक देश में जो भी पार्टी सरकार में रही, उसने यही मॉडल अपनाया है। देशभर के अखबारों में आये दिन केन्द्र और राज्य सरकारों के पूरे पेज के विज्ञापन देखने को मिलते हैं कि किस तरह से देश या राज्य की सरकारें गाजे–बाजे के साथ मेगा इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करते हैं। या फिर आये दिन यह भी खबरे मिलती है कि देश के बड़े लोन डिफाल्टर्स की सूची में सरकारों के चहेते रहे कौन–कौन से बडे उद्योगपति या प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल हैं।

6. जब से देश में ट्रिकल–डाउन–इकोनोमिक्स के मॉडल पर जोर दिया है लगभग तभी से, यानि 90 के दशक की लगभग शुरूआत से ही, दिल्ली में भी एक चुनी हुई सरकार की व्यवस्था लागू हुई। यह महज संयोग हो सकता है लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने भी लगभग शुरू से इसी आर्थिक मॉडल पर काम किया। सवाल उठता है कि इकोनोमी के इस परम्परागत मॉडल ने क्या डिलीवर किया है? अगर हम जीडीपी के संकुचित लैंस से देखें तो हां! हमारी इकोनोमिक ग्रोथ हुई है लेकिन देश के सब लोगों के नजरिये से देखेंगे तो समझ में आता है कि हमारे सामने विकास को लेकर नई–नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आज हर आदमी यह जानता है कि हम जॉब ग्रोथ के मामले में सबसे खराब स्थिति में पहुंच गये हैं। सरकार का अपना आर्गनाईज्ड व अनआर्गनाईज्ड लेबर–ब्यूरो–डेटा यह बताता है कि किस तरह 2013–14 के बाद से हम रोजगार वृद्धि की दर के मामले में आजादी के बाद से सबसे निचले पायदान पर जाकर खडे हुए हैं।

7. सबसे चिंताजनक संकेत 2018 की 'वर्ल्ड इन–इक्वालिटी रिपोर्ट' से मिलते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में आर्थिक असमानता किस तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जहां देश के महज 10 प्रतिशत लोगों की आय देश की कुल आय का करीब 56 प्रतिशत है। और टॉप के 0.1 प्रतिशत लोगों की ग्रोथ का आंकड़ा, निचले पायदान पर खड़ी 50 प्रतिशत आबादी की कुल ग्रोथ से ज्यादा है। आज हमारी आर्थिक असमानता की दर पहली बार अमेरिका, रूस और चीन से आगे पहुंच गयी है। ट्रिकल–डाउन–इकोनोमिक्स के पैरोकारों को यह आंकड़ा जरूर देखना चाहिए और देश के आर्थिक नीति निर्माताओं को इस सच्चाई को देखकर देश की आर्थिक नीति बनानी चाहिए।

8. अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्ताव किसी भी सरकार की आर्थिक नीतियों का ताना–बाना बुनता है। इसलिए आर्थिक नीतियों पर काम करने से पहले इन सवालों पर ध्यान देना जरूरी है कि –

- दुनिया की फास्टेस्ट–ग्रोइंग–इकोनोमी में होने का क्या फायदा है अगर हमारी सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का उतना प्रतिशत भी खर्च नहीं कर रही हैं जितना बाकी ब्रिक्स देश और कई सार्क देश कर रहे हैं।
- मेगा–इन्वेस्टर–समिट में एक के बाद एक अनगिनत समझौतों पर दस्तख़त करने का क्या फायदा है अगर हमारे 5 साल के कम उम्र के एक तिहाई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और कक्षा 6, 7 व 8 में पढ़ने वाले तीन चौथाई बच्चे अपनी टैक्स्ट बुक्स तक ठीक से नहीं पढ़ पाते है।
- लाखों करोड़ों डॉलर्स का विदेशी निवेश किस काम का है, अगर हमारे इंजीनियरिगं कालेजों से निकलने वाले स्नातकों में से सिर्फ 7 प्रतिशत ही एमप्लोएबल हैं। और देश में लगभग हर सैक्टर में स्किल्ड मैन–पावर की भारी कमी है।
- मेक–इन–इंडिया में हम विदेशी निवेशकों को तो बुला सकते हैं, हम स्मार्ट सिटीज की बड़ी–बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं लेकिन अगर दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 शहर भारत के हैं और हमारे कस्बे से लेकर जिला मुख्यालयों तक सारे शहर ट्रैफिक जाम और धूल भरी सड़कों से अटे पड़े हैं तो चंद समार्ट सिटी देश की इकोनोमी में क्या योगदान करेंगे।

9. इसी संदर्भ में मैने आर्थिक परिदृश्य पर अपनी बात शुरू की थी कि दिल्ली में पिछले 3 साल में ट्रिकल–डाउन की जगह ट्रिकल–अप–इकोनोमिक मॉडल को अपनाया गया है।

ट्रिकल–अप–इकोनोमी का सीधा सा मतलब है कि सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां बनाये जिनका सीधा लाभ गरीब और मिडल क्लास नागरिकों को मिले और उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े, वो स्वस्थ रहें और उनकी आय भी बढ़े। यही इस सरकार का एकमात्र नारा है – 'शिक्षित राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र'। यह हमारा कोई जुमला नहीं है यह वो नारा है जो हमने पिछले तीन साल के काम से निकाला है। सरकार यह भरोसा रखे कि जब गरीब ओर मिडल क्लास की समृद्धि बढ़ेगी तो ही ओवरऑल इकोनोमी भी आगे बढ़ेगी।

10. अध्यक्ष महोदय, इसी नीति पर काम करते हुए वित मंत्री के रूप में हमने अपनी सरकार के पहले बजट में शिक्षा का बजट लगभग दोगुना किया था और स्वास्थ्य का बजट डेढ़ गुना किया था। पिछले तीन साल से हम लगातार अपने सलाना बजट का करीब एक चौथाई हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं जो ना सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि सारे राज्यों के औसत शिक्षा खर्च – 15.6 प्रतिशत से कहीं अधिक है। आम आदमी के लिए अच्छे स्कूल बनाकर और सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराकर हम उसकी आर्थिक मजबूती पर सीधे असर डाल रहे हैं।

11. इसी तरह आम आदमी को बेहतरीन मौहल्ला क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक और जन उपयोगी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली के आम परिवार की मेहनत की कमाई मोटे–मोटे मेडिकल बिल्स पर न खर्च हो। पिछले 3 साल में दिल्ली में हमने स्वास्थ्य पर अपने सलाना बजट का 11.3 प्रतिशत रखा है जबकि आपको हैरानी होगी कि सारे राज्यों का कुल औसत 4.9 प्रतिशत तक सीमित है। मैं यहां इस बात को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे के साथ–साथ हम पर्यावरण पर भी काफी काम कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण का सीधा असर

लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए सरकार इस साल पहली बार ग्रीन बजट भी लेकर आयी है।

12. हमारी सरकार ने अफोर्डेबल कोस्ट पर बिजली उपलब्ध कराई है। पिछले 3 साल से दिल्ली के नागरिकों को देश के किसी भी बड़े शहर की तुलना में सस्ती बिजली मिल रही है। इसी तरह निःशुल्क पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की योजना से न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को सीधे आर्थिक फायदा पहुंचाया है बल्कि 20 किलोलीटर की मासिक सीमा होने के कारण लोगों में पानी बचाने की प्रवृति भी बढी है और बड़ी संख्या में लोगो ने पानी के वैध कनेक्शन लिये हैं। इन योजनाओं की बदौलत सरकार ने 400 नई कालोनियों में घर–घर में पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले ऐसे कई खर्चों को सरकार की नीतियों ने कम किया है जिससे वे इस पैसे को अपने परिवार की खुशहाली के लिए बाज़ार में या अपने खुद के बिजनेस आदि पर खर्च कर सकते हैं और अंततः इसका लाभ दिल्ली की इकोनोमिक ग्रोथ के रूप में सबको मिल रहा है। यही वजह है कि हमने दिल्ली में मैट्रो किराये में दोगुना वृद्धि का भी पुरज़ोर विरोध किया था।

13. ट्रिकल–अप–इकोनोमी की दिशा में हमारी सरकार का एक सबसे बड़ा कदम रहा है – न्यूनतम मजदूरी की सीमा बढ़ाना। पिछले साल ही दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। देश में आज सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में मिलती है। यह ऐसी नीति है जिससे दिल्ली में मेहनत करने वाले परिवारों के जीवन में सीधे–सीधे आर्थिक सुधार आ रहा है। इसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और गेस्ट टीचर्स का वेतन भी ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया गया। क्योंकि हमे विश्वास है कि उनकी आर्थिक प्रगति से ही पूरी दिल्ली की आर्थिक प्रगति जुड़ी हुई है।

14. अध्यक्ष महोदय, ऊपर दिये गये तथ्य इस बात का प्रमाण हैं कि किस तरह से दिल्ली का ट्रिकल–अप–इकोनोमिक मॉडल ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आज पूरे देश की आवश्यकता है। हमारा एक ही मंत्र है कि अगर दिल्ली के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, उन्हे अच्छी शिक्षा मिलेगी और उनके परिवार की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित ही दिल्ली प्रगति करेगी और इसके नतीजे दिल्ली के सामने हैं। दिल्ली की ग्रोस–स्टेट–डोमस्टिक–प्रोडक्ट (जीएसडीपी) ग्रोथ लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली सरकार का बजट जो कि 3 साल पहले 30,900 करोड़ रूपये था, इस साल डेढ़ गुणा से ज्यादा बढ़ गया है। हमें खुशी है कि हमारी सरकार का इकोनोमिक मॉडल दिल्ली के विकास में सहयोग कर रहा है।

आर्थिक परिदृश्य

15. अध्यक्ष जी, नोटबंदी के नकारात्मक प्रभाव और जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यवधान के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था स्थायी विकास के सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2017–18 में बढ़ कर 6,86,017 करोड़ रुपये पर पहुंच जाने की संभावना है, जो 2016–17 में 6,16,826 करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें 11.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर वास्तविक संदर्भ में दिल्ली के जीएसडीपी की वृद्धि दर 2017–18 में 8.14 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6.6 प्रतिशत है। दिल्ली के जीएसडीपी में वास्तविक वार्षिक औसत बढ़ोतरी 2015–16 से 2017–18 की अवधि में 9.1 प्रतिशत रही है, जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में बढ़ोतरी 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

16. राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2011–12 के 3.94 प्रतिशत से बढ़ कर 2017–18 में 4.10 प्रतिशत हो गया। यह उपलब्धि इसके बावजूद प्राप्त हुई है कि देश की कुल आबादी में दिल्ली की हिस्सेदारी केवल 1.4 प्रतिशत है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की प्रमुखता है, जिसकी हिस्सेदारी ग्रोस–स्टेट–वैल्यू–एडिशन में 85.92 प्रतिशत है। इसके बाद 12.04 प्रतिशत योगदान माध्यमिक क्षेत्र का और 2.04 प्रतिशत योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है।

17. दिल्ली की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय वर्तमान मूल्यों पर 2017–18 में बढ़कर 3,29,093 रुपये हो गई, जो 2016–17 में 3,00,793 रुपये थी। इस तरह 2017–18 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय में 9.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो एक अच्छा संकेत है।

18. राष्ट्रीय औसत से तुलना करें, तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय स्तर की 1,12,764 रुपये की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 2.92 गुना अधिक है।

संशोधित अनुमान

19. अध्यक्ष जी, चालू वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान 44,370 करोड़ रुपये के प्रस्तावित हैं, जबकि बजट अनुमान में यह राशि 48,000 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई थी। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में खर्च की गई 37,263 करोड़ रुपये की राशि से 19.07 प्रतिशत अधिक हैं। 44,370 करोड़ रुपये के प्रस्तावित संशोधित बजट में राजस्व व्यय के लिए 36,326 करोड़ रुपये और पूंजी व्यय के लिए 8,044 करोड़ रुपये शामिल हैं। स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के रूप में 2017–18 के बजट अनुमान में अनुमोदित 29,500 करोड़ रुपये 2017–18 के संशोधित अनुमान में घट कर 28,370 करोड़ रुपये रह

गए हैं। यह बचत सरकार द्वारा जनता के धन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से किए जाने का परिणाम है। कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत बजट में निर्धारित और अनुमोदित परिव्यय 18,500 करोड़ रुपये को संशोधित अनुमानों में कम करके 16,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। यह राशि 2016–17 में खर्च की गई 14,104 करोड़ रुपये की तुलना में 13. 44 प्रतिशत अधिक है। ऋण–जीएसडीपी अनुपात 2014–15 के 6.57 प्रतिशत से घट कर 2017–18 में 5.03 प्रतिशत रह गया है जोकि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। इस प्रकार यह हमारे बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है।

2017–18 के लिए पूरक अनुदान मांग

20. अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमान के अनुसार 1170.29 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगें अपेक्षित हैं। इसलिए मैं पूरक मांगों के लिए सदन की मंजूरी चाहता हूँ।

बजट अनुमान 2018–19

21. अध्यक्ष जी, मैं अगले वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ –

- वर्ष 2018–19 के लिए कुल बजट अनुमान 53,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 43,092 करोड़ रुपये और पूंजी व्यय के लिए 9908 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय पूरा करने के बाद वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान के अनुसार हमारे पास 4,465 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष रहेगा, जो कि वर्ष 2017–18

के बजट अनुमान में यह राशि 3,789 करोड़ रुपये, और वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान में 3,921 करोड़ रुपये थी।

- मैं स्थापना व्यय और प्रतिबद्ध देयताओं, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, भारत सरकार को ब्याज और मूलधन के भुगतान, जल और विद्युत सब्सिडी, डीटीसी को प्रचालन घाटा पूरा करने के लिए अनुदान, आदि के लिए 31,000 करोड़ रुपये और विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पूंजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 22,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।
- 53,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के लिए वित्तीय संसाधन में –
    - 42,000 करोड़ रुपये कर राजस्व से,
    - 800 करोड़ रुपये गैर–कर राजस्व से,
    - 550 करोड़ रुपये पूंजी प्राप्तियों से,
    - 2,924 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण से,
    - 3,307 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों से,
    - 450 करोड़ रुपये सामान्य केंद्रीय सहायता से,
    - 325 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से,
    - 675 करोड़ रुपये भारत सरकार से अन्य प्राप्तियों के रूप में और
    - शेष धन अपने प्रारंभिक शेष से जुटाए जाएंगे।
- वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित बजट राशि 53,000 करोड़ रुपये, वर्ष 2017–18 के 44,370 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 19.45 प्रतिशत और 48,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 10.42 प्रतिशत अधिक है।

<u>स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता</u>

22. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार वर्ष 2018–19 में स्थानीय निकायों को 6,903 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो कुल बजट का 13 प्रतिशत है तथा वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान में वर्णित राशि की तुलना में 9.88 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगमों की खस्ता हालत को देखते हुए, हमने वर्ष 2017–18 और वर्ष 2016–17 में बकाया ऋण देयताओं की मूलधन और ब्याज राशि उन्हें जारी किए जाने वाले अनुदानों में से वसूल नहीं की है। स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में मुख्य रूप से वर्ष 2018–19 में कर वसूली में 3,460 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क तथा एकबारगी पार्किंग शुल्क में 1,805 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी शामिल है।

23. इस वर्ष सरकार दिल्ली की ऐसी सड़कों और गलियों को ठीक करने के लिए, जिन्हे ठीक करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है, लेकिन वे टूटी पड़ी हैं या बनी नहीं हैं, ऐसी सड़कों के लिए 1,000 करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था कर रहे है। इस पैसे के इस्तेमाल से सारी दिल्ली की छोटी–छोटी सड़कों और गलियों को ठीक कराया जायेगा। हमें उम्मीद है कि आदरणीय उपराज्यपाल महोदय नगर निगम से इन सड़कों को ठीक कराने के लिए एनओसी दिलवा देगें। सभी स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 638 करोड़ रुपये की राशि भी दी जा रही है।

24. अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने पहला बजट पेश किया था तो उसे हमने शिक्षा, स्वास्थ्य बजट का नाम दिया था। पिछले वर्ष पेश बजट में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ बजट–आउटकम्स यानि जनता के टैक्स के पैसे को खर्च करके उससे मिलने वाले

आउटकम पर ज़ोर दिया और इसलिए उसे हमने आउटकम बजट कहा। इस वर्ष मैं इस बजट में ग्रीन बजट के नाम से एक और महत्वपूर्ण अंग जोड़ रहा हूॅ।

ग्रीन बजट

25. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की ओर से दिल्ली का पहला ग्रीन बजट इस सदन के समक्ष रख रहा हूॅ और संभवतः यह देश में किसी भी सदन में पेश किये जाने वाला पहला ग्रीन बजट है। हमने पिछले कई महीनो में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की बहुत सारी सम्भावनाओं पर अध्ययन किया है और उससे निकले निष्कर्षों और योजनाओं को हम इस बार बजट प्रस्तावों में ला रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा सम्भवतः देश में यह पहला प्रयास है कि सरकार के विभिन्न विभागों की प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वैज्ञानिक अध्ययन करके उन्हे बजट प्रस्तावों में शामिल कर रहे हैं।

26. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली सरकार के चार विभागों – पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के 26 कार्यक्रमों एवं योजनाओं को एक सूत्र में पिरो कर उन्हे प्रदूषण नियंत्रण के एकीकृत प्रयास अभियान के रूप में जोड़ने की तैयारी की है। हमने सस्टेनेबल डेवलेपमेंट पर काम कर रहे ग्लोबल–थिंक–टेंक 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' के साथ सहभागिता करके यह समझने की कोशिश भी की है कि वित वर्ष 2018–19 के लिए दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट प्रस्तावों का दिल्ली में प्रदूषण पर क्या असर पड़ेगा। मुझे सदन के समक्ष यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 26 ग्रीन बजट प्रस्तावों के प्रयास से प्रतिवर्ष दिल्ली में प्रदूषण उत्सर्जन में अनुमानित कमी इस प्रकार रहेगी –

- कार्बन डाइऑक्साईड (CO_2) : 20,98,000 मीट्रिक टन
- पी एम 2.5 : 503 मीट्रिक टन

- नाईट्रोजन ऑक्साईड (NO_x) : 4,540 मीट्रिक टन
- सल्फर ऑक्साईड (SO_x) : 9,364 मीट्रिक टन
- वोलेटाईल आर्गेनिक (VOC) : 11,515 मीट्रिक टन
- अमोनिया : 136 मीट्रिक टन

27. ग्रीन बजट तैयार करने की प्रक्रिया में हमने अनुभव किया कि दिल्ली सहित देश के किसी भी शहर के बारे में ऐसी कोई फेहरिस्त तैयार नहीं की गयी है जिससे पता चल सके कि उस शहर की हवा में सालभर किस–किस तरह के प्रमुख प्रदूषणकारी तत्व उत्सर्जित होते हैं। न ही हमारे पास इस तरह की कोई फेहरिस्त है जिससे यह पता चल सके कि साल के किस महीने या मौसम में वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले तत्व किन–किन कारणों से कब–कब बढ़ते हैं। अगर हमें प्रदूषण जैसी भयावह समस्या को नियंत्रण में लेना है तो शहरों के लिए यह डेटा बहुत जरूरी है। वित वर्ष 2018–19 में दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां प्रदूषणकारी तत्वों का रियल–टाईम–डेटा पूरे साल इकटठा किया जायेगा। और उनके कारणों का निरंतर अध्ययन किया जायेगा। यह कार्य वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया जा रहा है।

28. इसी के साथ–साथ पूरी दिल्ली में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की फेहरिस्त बनाने का काम भी पहली बार शुरू होगा। यह कार्य विश्व के सबसे बड़े शहरों के समूह सी–40 सिटीज–फॉर–क्लाईमेट–लीडरशिप के साथ मिलकर शुरू किया जायेगा।

29. अध्यक्ष महोदय, अब मैं ग्रीन बजट से संबंधित विभागवार योजनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ।

30. पर्यावरण विभाग –

- पर्यावरण को साफ–सुथरा रखना है तो सबसे जरूरी है पेड़ यानि की ग्रीन कवर बढ़ाना। दिल्ली में अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने के दिशा में सरकार पिछले 3 साल से मिशन–मोड में काम कर रही है। इस साल दिसंबर 2017 तक 5.5 लाख पौधे पहले ही लगाए जा चुके थे। मार्च 2018 तक तीन लाख और पौधे लगाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा डिवाइडर और सड़क के किनारों पर सिविल एजेंसियों द्वारा 7.93 लाख छोटे पेड़–पौधे लगाये गये। नागरिकों को 3.5 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए गए ताकि वे अपने घरों के आगे पीछे आंगनो में उन्हें लगा सकें। इन प्रयासों से अच्छे परिणाम सामने आए और दिल्ली का हरित क्षेत्र 2015 में 299.77 वर्ग किलोमीटर से बढ़ कर 2017 में 305.41 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगले साल सरकार आरडब्ल्यूए मार्किट एसोसिएशन और एनजीओ के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पोघे लगाने की तैयारी में है। इसके लिए एयर–एंबियंस–फंड का इस्तेमाल किया जायेगा।
- मैंने पिछले बजट में घोषणा की थी कि दिल्ली को कीकर–मुक्त बनाया जाएगा। सेंट्रल रिज एरिया में विलायती कीकर के स्थान पर नए पौधे लगाने की एक दीर्घावधि योजना शुरू कर दी गई है।
- गगनचुंबी कंकरीट इमारतों से लेकर अनियमित कालोनियों तक के बीच हरे–भरे क्षेत्र विकसित करने के लिए शास्त्री पार्क, ताज एन्क्लेव, नसीरपुर, मुखमेलपुर और मित्राऊं में कई सिटी–फारेस्ट विकसित किए गए हैं। इसके अलावा तुगलकाबाद में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। 2018–19 में जोनापुर, आया नगर, डेरा मांडी, बेला फार्म, गढ़ी मांडू पाकेट ए और अलीपुर में नए सिटी–फारेस्ट विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सेंट्रल

रिज में वॉकिंग–ट्रेल विकसित किए जाएंगे, जिनसे नागरिकों को दिल्ली में ही घने वृक्षों के बीच सांस लेने का मौका मिलेगा। इस योजना को माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

- दिल्ली को हरा–भरा बनाये रखने के अलावा प्रदूषण से लड़ने के लिए कई नई प्रोत्साहन योजनायें भी सरकार ने तैयार की हैं। सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इंडस्ट्रीयल यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी।
- इसी तरह दिल्ली के रेस्टोरेंटस को भी कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक या गैस तंदूर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देंगे। और इसके लिए 5 हजार रूपये प्रति तंदूर तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी।
- साथ ही 10 केवीए या इससे अधिक क्षमता के डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले व्यवसायियों को भी स्वच्छ ईंधन पर आधारित इलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इसके लिए 30 हजार रूपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जायेगी।
- दिल्ली के नागरिकों को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बनाने और इसके खतरे के प्रति, हर पल सतर्क बनाने के उद्देश्य से पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी कार्यालयों में वायु प्रदूषण के लेवल की जानकारी देने वाले करीब एक हजार इंडोर डिस्पले पैनल लगाये जायेंगे।

- दिल्ली में वायू प्रदूषण की स्थिति के पूर्वानुमान के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से एक मॉडल डेवलप किया जायेगा ताकि किसी विशेष परिस्थिति के कारण, जैसे कि सर्दी के दौरान दिल्ली में स्मॉग की मात्रा अचानक बढती है, इनकी जानकारी पहले से हो सके।

31. परिवहन विभाग –

- हमारी सरकार दिल्ली के डीटीसी और क्लस्टर बस सहित संपूर्ण बस बेड़े को वातावरण अनुकूल फ्यूल टेक्नोलाजी के ओर ले जाने के प्रति संकल्पबद्ध है। आगामी वर्ष में हम दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह देश के किसी भी शहर में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बडा बेड़ा होगा। और वस्तुतः चीन को छोडकर दुनिया के किसी भी देश में सबसे बड़ा। इस योजना को माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यह कदम साबित करता है कि हमारी सरकार दिल्ली के लोगों के लिए कितनी समर्पित है और हम दिल्ली को आधुनिक, प्रभावशाली, भरोसेमंद और वातावरण अनुकूल बस परिवहन व्यवस्था देने में कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ना चाहते।
- इसके साथ–साथ परिवहन विभाग मेट्रो स्टेशन्स के पास लास्ट–माइल–कनेक्टिविटी देने के लिए डीएमआरसी के बेड़े में भी 905 इलेकट्रिक फीडर व्हीकल शामिल कराने में मदद कर रहा है।
- मैंने 2016–17 के बजट में ई–रिक्शा मालिकों को 30,000 रूपये की एकबारगी सब्सिडी देने की घोषणा की थी। हमारी सरकार ने यह फैसला भी किया है कि यह लाभ उन सभी ई–रिक्शा मालिकों को भी दिया जाए जो 1 जुलाई 2015 से 1 अप्रैल 2016 के बीच

पंजीकृत किए गये हैं। इस तरह 1 जुलाई 2015 से 1 अप्रैल 2016 के बीच पंजीकृत सभी ई–रिक्शा मालिकों को 30,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी, भले ही उनके आवेदन विभाग में विचाराधीन हों या उन्होंने नए सिरे से आवेदन किया हो। इसके अतिरिक्त एयर–एंबीयंस–फंड से 15,000 रूपये उन ई–रिक्शा मालिकों को भी दिए जाएंगे जिन्हें 15,000 रूपये की पुरानी दर से भुगतान किया गया था।

- दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए सरकार विस्तृत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर रही है इसमें खास करके बीएस–2 एवं बीएस–3 दोपहिया वाहनों, टैक्सी और कमर्शियल गुड्स कैरियर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का खाका बनाया जायेगा।
- निजी उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली इलैक्ट्रिक कारों पर तो सरकार पहले ही सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही निजी कारों के खरीदारों के लिए पैट्रोल अथवा डीजल की जगह सीएनजी–फैक्ट्री–फिटेड कार खरीदने पर सरकार 50 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्जेज में छूट का प्रावधान करेगी। इस योजना को भी माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद लागू किया जा सकेगा।
- दिल्ली में ओवरलोडेड ट्रक्स के खिलाफ अभियान चलाने के लिए परिवहन विभाग के एनफोर्समेंट विंग को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए बुराड़ी, सराय काले खां और द्वारका स्थित इंपाउडिंग पिट्स पर वेंइग–ब्रिज बनाये जायेंगे। निगरानी के लिए 60 नये वाहन, बाडी–कैमरा और ई–चालानिंग टैब खरीदे जायेंगे।
- वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पोल्यूशन–अंडर–कन्ट्रोल (पीयूसी) प्रोग्राम को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है इसके तहत वाहन मालिकों को एसएमएस अथवा फोन से

रिमांइडर भेजना और पीयूसी सेंटर्स का थर्ड–पार्टी–ऑडिट कराने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलाजी संस्थान एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स के साथ काम किया जा रहा है।

32. ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रिनुएबल एनर्जी के लिए कई ऐसी पहल की जा रही हैं जिससे दिल्ली में फॉसिल–फ्यूल आधारित बिजली उत्पादन पर दिल्ली की निर्भरता कम से कम हो सके। दिल्ली में कुल रिनुएबल एनर्जी क्षमता फरवरी 2018 तक 133.13 मेगावाट थी, जिसमें 81.13 मेगावाट सौर ऊर्जा और 52 मेगावाट कचरे से ऊर्जा संयंत्रों से मिलने वाली बिजली शामिल है। 74 मेगावाट सौर ऊर्जा संवर्धन का कार्य प्रगति पर है। इससे दिल्ली में कार्बन एवं अन्य प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन नीचे लाने में सफलता मिलेगी।

- सरकार सौर एवं पवन आधारित बिजली उत्पादन केन्द्रों से आने वाले वर्षों में 1,000 मेगावाट ग्रीन पावर खरीदेगी।
- दिल्ली में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीमित समय के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं द्वारा लगाये गये सौर ऊर्जा नैट मीटर कनेक्शन से, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, तीन साल के लिए 2 रूपये प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा खरीदने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- हमारी सरकार स्कूलों, मंडियों और विभिन्न सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयत्रं लगवाने के लिए एक ग्रुप–नैट–मीटरिंग पॉलिसी लायेगी ताकि दिल्ली में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सके।

- इस वर्ष के ग्रीन बजट में सरकार पायलट स्तर पर एग्रीकल्चर–कम–सोलर–फार्म–स्कीम के नाम से एक नई योजना ला रही है। इसके तहत दिल्ली के खेतों में फसल की उंचाई से ऊपर उठा कर सोलर पैनल स्थापित करने को प्रोत्साहन देने की योजना है। प्रयोग दुनिया भर में हो रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसान सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ अपनी खेती भी जारी रख पाते हैं। इससे दिल्ली में खेती–बाड़ी में लगे लोगों को अतिरिक्त आय होगी।
- सरकार बिल्डिंग एनर्जी एफिसेंसी प्रोग्राम अगले साल से लागू करने जा रही है। इसके तहत विभिन्न कार्यालयों, इमारतों का पावर कंजम्पशन ऑडिट किया जायेगा। इसकी शुरूआत ऊर्जा विभाग अपने अधीन इमारतों से करेगा।
- सरकार अगले वर्ष से दिल्ली में बनने वाली नई कमर्शियल बिल्डिंग्स पर बिजली खपत कम करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (इसीबीसी) लागू करेगी। यह कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक की खपत वाली इमारतों या 500 वर्गमीटर से बड़े प्लाट पर बनी इमारतों पर लागू होगा। यह योजना भी माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी मिलने के बाद लागू होगी।

33. लोक निर्माण विभाग

- दिल्ली में सड़क किनारे और वाहनों से उड़ने वाली धूल, प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों की लैंडस्केपिंग की योजना ला रही है। इसके तहत सड़क पर धूल न उड़े, इसके लिए सड़कों के आस–पास की सभी कच्ची जगहों को घास व पौधे लगाकर उसे सुसज्जित किया जायेगा। इसके लिए भी माननीय उपराज्यपाल महोदय के सहयोग की जरूरत पड़ेगी।
- लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी लाईट्स को एलईडी लाईट्स में बदलने का काम एस्को मॉडल के तहत किया जायेगा।
- लोक निर्माण विभाग की सड़को पर एक पायलट योजना के तहत 16 कि.मी. लंबे साईकिल ट्रैक पर सौर ऊर्जा पैनल लगाये जायेंगे।

34. मुझे पूरा यकीन है कि इन सब प्रयासों से दिल्ली के वातावरण में प्रदूषण का प्रभाव कम करने में काफी मदद मिलेगी। कई योजनाओं के लिए सरकार ने अलग से फंड की व्यवस्था की है और कई योजनाओं के लिए एयर एंबियेंस फंड और एनवार्यमेंट कम्पनसेशन चार्ज का इस्तेमाल किया जायेगा। लेकिन यहां मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली में प्रदूषण से सिर्फ दिल्ली के लिए योजनायें बनाकर नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसी तरह का अभियान चलाना होगा। एनसीआर में शामिल सभी सरकारों को इसमें शामिल होना होगा और यह तभी संभव है जब केन्द्र सरकार इसमें पहल करेगी।

35. अध्यक्ष महोदय, अभी तक मैंने जितने प्रस्ताव रखे वह दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दिल्ली को हरा–भरा एवं प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए एकीकृत प्रयासों का एक साथ प्रस्तुतिकरण था। अब मैं आपके समक्ष अलग–अलग क्षेत्रों के कुछ और प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

ऊर्जा

36. अध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले बिजली की मंहगाई दिल्ली में एक बड़ी समस्या थी। आसमान छूती कीमतें और उस पर लगभग हर साल कीमतों में बढ़ोतरी। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही दिल्ली के आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आधे दाम में बिजली उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। और तब से यानि पिछले 3 साल में दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। सस्ती बिजली से दिल्ली के आम आदमी के परिवार की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, दिल्ली की ओवर–ऑल इकोनोमी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज दिल्ली में करीब 37.28 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 3 साल पहले के मुकाबले आधे दाम पर बिजली मिल रही है जो कि दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं का 82.84 प्रतिशत हैं। यह योजना आगे भी जारी रहेगी और इसके लिए बजट में 1,720 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

37. मैं 2018–19 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2,190 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं।

परिवहन

38. मान्यवर, दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहनों की कुल संख्या अन्य महानगरों में पंजीकृत निजी वाहनों की संख्या से बहुत अधिक है। इससे न केवल सड़कों पर भारी वाहनों की भीड़ रहती है बल्कि सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और ईंधन व्यर्थ होता है। इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए निरंतर और अथक प्रयास कर रही है।

39. डीटीसी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को उनका वेतन और अन्य भत्ते समय पर मिलते रहें यह सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने डीटीसी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुसार बकाया भुगतान एवं डीटीसी पेंशनधारियों का महँगाई भत्ता आदि देने के लिए अतिरिक्त संशाधनों का प्रस्ताव है। इससे सभी बकाया भुगतान किये जा सकेंगे और इसका लाभ 41,000 कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा। डीटीसी के आपरेटिंग व्यय एवं उपरोक्त निर्णय की पूर्ति के लिए वर्ष 2017–18 में बजट अनुमान 1,642 करोड़ रूपये से बढ़ाकर संशोधित अनुमान 2,107 करोड़ रूपये किये जाने का प्रस्ताव है।

40. दिल्ली में आटोरिक्शा परमिट का मुद्दा कई सालों से लंबित पड़ा था। 2017–18 के दौरान सरकार ने अथक प्रयास करके 10,000 नये आटो परमिट को मंजूरी दी। इसमें से 8,600 परमिट जारी किये जा चुके हैं और बाकि जल्द जारी कर दिये जायेंगे।

41. दिल्ली में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 12 आटोमोटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक पर काम शुरू किया है। मारूति सुजुकी फाउंडेशन की सहभागिता से यह योजना 2018–19 में पूरी हो जायेगी। इसका उद्देश्य है ड्राइविंग टेस्ट लेते वक्त कम से कम मानवीय हस्तक्षेप और उसकी बारीकियों को तकनीकी मदद से जांचना। सरकार अगले कुछ हफ्तों में रोड़ सेफ्टी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करेगी और जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिए रोड़ सेफ्टी फंड भी स्थापित किया जायेगा।

42. 2018–19 के दौरान डीटीसी के बेड़े में स्टेण्डर्ड साइज की 1,000 बसें जोड़ने का काम शुरू हो जायेगा। मैं, डीटीसी द्वारा बसों की खरीद के लिए 2012–13 में जारी की जा चुकी 199.

55 करोड़ रुपये की राशि के अलावा 2018–19 में 150 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं।

43. इसी के साथ–साथ लगभग 1,000 और नई क्लस्टर बसें चलाई जायेंगी। मैं क्लस्टर बसों की Viability Gap Funding के लिए 2018–19 में 450 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं।

44. बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकटिंग के जरिए स्वतः किराया एकत्र करने की व्यवस्था क्लस्टर बसों में पूरी तरह लागू कर दी गई है। डीटीसी ने भी अपनी बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीन प्रणाली लागू करना शूरु किया है। एक ही मोबिलीटी कार्ड की सुविधा की एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत जनवरी 2018 से डीटीसी की 200 और 50 क्लस्टर बसों में शुरु की गई है। इसे अप्रैल 2018 से सभी बसों मे लागू किये जाने की योजना है। इनमें ईटीएम का इस्तेमाल करते हुए किराए का भुगतान दिल्ली मेट्रो रेल कार्ड के जरिए किया जा सकेगा।

45. डीटीसी द्वारा खरीदी जाने वाली नई बसों और क्लस्टर योजना के तहत शामिल की जाने वाली बसों की पार्किंग के लिए 7 बस डिपो – ढिचाऊं कलां–2, बवाना सेक्टर–1, रेवला खानपुर, रानी खेड़ा–1, रानी खेड़ा–2, रानी खेड़ा–3 और द्वारका सेक्टर 22 में पूरे कर लिए गये हैं। खरखरी नहर का बस डिपो मार्च, 2018 में पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2018–19 में 6 नये बस डिपो घुम्मन हेड़ा, मुण्डेला कलां, रोहिणी सेक्टर–37, ईस्ट विनोद नगर, बवाना सेक्टर–5 एवं वीआइयू बुराड़ी भी बनाए जाएंगे। इनके लिए मैं 80 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं।

46. हमारी सरकार ने सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन के लिए कई कदम उठाए हैं। डीटीसी की रात्रि सेवा में विस्तार कर 24 मार्गों पर 85 बसें चलाई जा रही हैं जबकि पहले 8 मार्गों पर 38 बसें

ही चलती थी। डीटीसी, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस चालकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का एक कार्यक्रम निरंतर चला रहा है। महिला यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए डीटीसी की बसों में 2,370 सिविल डिफेंस मार्शल और 120 होम गार्ड तैनात किये गये हैं।

<u>शिक्षा</u>

47. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार दिल्ली को एक शैक्षिक केंद्र बनाने की दिशा में दूरदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही है। 2018–19 के बजट आबंटन में शिक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 26 प्रतिशत है। मैं 2018–19 में शिक्षा के लिए 13,997 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 13,238 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 759 करोड़ रुपये पूंजी व्यय से सम्बद्ध हैं। शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 6,019 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित 6,019 करोड़ रुपये का परिव्यय 2017–18 के संशोधित अनुमानों में प्रस्तावित शिक्षा क्षेत्र के 3,083 करोड़ रुपये के परिव्यय से 95 प्रतिशत अधिक है, एवं 3,525 करोड़ रूपये बजट अनुमान से 70 प्रतिशत अधिक है।

48. शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त क्लास रूम, नए स्कूल भवन, खेल के मैदान, स्वच्छ शौचालय सुविधाओं आदि के निर्माण के संदर्भ में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के संवर्धन के लिए भारी निवेश को प्राथमिकता दी गयी है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, वर्तमान विद्यालयों में प्री–स्कूल कक्षाएं शुरू करना, शिक्षण को दिलचस्प बनाना, और शिक्षा को खेल गतिविधियों के साथ जोड़ना, आदि ऐसे सम्भावना वाले क्षेत्र हैं, जिन पर दिल्ली सरकार 2018–19 के दौरान जोर देगी। सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार लाने, उच्चतर शिक्षा में अधिक शैक्षिक

अवसर प्रदान करने, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के जरिए उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

49. हमारी सरकार ने पहले साल में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को दुरस्त करने का काम तेजी से किया। अब यह काम अपनी गति पकड़ चुका है। इसके बाद दूसरे व तीसरे वर्ष से शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने और उन्हे विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दिलाने का काम शुरू किया। यह कार्य भी अब अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। अगले साल से हमारी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलो में एक नया पाठयक्रम – हेप्पीनेस करिकुलम के नाम से लेकर आ रही है। इसके तहत नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां विकसित की जा रहीं है, ताकि कम आयु में ही बच्चों को प्रसन्न रहने, आत्मविश्वास अर्जित करने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐसे घटक शामिल किए जाएंगे, जो आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने वाले और तनाव एवं चिंता कम करने वाले हों और साथ ही निराशा से बचने में मददगार और शिक्षा एवं कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता सृजित करने वाले, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने वाले हों। शिक्षा में ऐसा समग्र दृष्टिकोण अपनाने से बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण और उन्हें खुशहाल जिंदगी जीने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।

50. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बदलाव आया है उसमें स्कूल मैंनेजमेंट कमिटी यानि एसएमसी का बड़ा योगदान रहा है। एसएमसी के 16 सदस्यों में से 12 अभिभावक होते हैं। इस सामुदायिक भागीदारी से स्कूलों में जवाबदेही बढ़ी है। इसलिए इस वर्ष से हर स्कूल की एसएमसी को 5 लाख रूपये का फंड दिया जायेगा जिससे वो स्कूल में लाईब्रेरी के लिए किताबें खरीदने, पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों की सुविधा हेतु टीचिंग ऐडस खरीदने

व छोटी–मोटी मरम्मत के काम करा सकेगी। साथ ही एसएमसी शॉर्ट–टर्म–बेसिस पर रिसोर्स पर्सन रख पायेगी। जो छात्रों को म्यूजिक, आर्ट, डांस, आईआईटी–मेडिकल की तैयारी या एक्सट्रा क्लास करा सकेगी। इस फंड के इस्तेमाल के निर्णय एसएमसी की मीटिंग में ही होंगे। इसके लिए स्कूल किसी पर निर्भर नहीं होगा।

51. हमने पिछले 2 सालों में मेगा पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि हम मानते हैं शिक्षा सफल होने के लिए स्कूल और घर के सम्मिलित प्रयास की जरूरत है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स वर्कशॉप भी शुरू करेंगे ताकि माता–पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकें।

52. शिक्षा अधिकार अधिनियम के संदर्भ में स्टूडेंट–टीचर रेश्यो बनाए रखने के लिए शैक्षिक ढांचे में निरंतर बढ़ोतरी के प्रयास किए गए हैं और सरकार ने 2018–19 में अनेक नई पूंजी परियोजनाओं की योजना बनाई है। हमने 12,748 अतिरिक्त क्लासरूमस के निर्माण, 30 नए स्कूल बिल्डिंग और 366 सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई है। 155 सर्वोदय विद्यालयों में प्री–प्राईमरी कक्षायें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार ने 144 स्कूलों में वाणिज्य विषय की पढ़ाई भी शुरू की है।

53. एलीमेंट्री कक्षाओं के बच्चों द्वारा अपनी टेस्टबुक पढ़ने और बेसिक मैथ स्किल डेवलप करने के उद्देश्य से सरकार ने 'चुनौती 2018' कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अच्छे नतीजों को देखते हुए अब इसी तर्ज पर 'मिशन बुनियाद' के नाम से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली सरकार और नगर निगम के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की रीडिंग और मैथ स्किल्स ठीक करने पर अप्रैल, मई और जून के महीनों में विशेष अभियान चलाया जायेगा।

54. विद्यार्थियों की संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल गतिविधियों पर समुचित निगरानी रखने के लिए सभी सरकारी स्कूल भवनों में करीब 1.2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 2018–19 के बजट अनुमानों में 175 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक भवन में 150 से 200 तक कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह भी है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के क्लासरूम की गतिविधियां सीधे इंटरनेट पर देखने की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

55. अध्यापकों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग के साथ–साथ सरकार उन्हे आधुनिक सुविधायें देने पर भी जोर दे रही है। अभी तक अध्यापकों का बहुत सारा समय हर महीने बच्चों की सूचियां बनाने व रिजल्ट तैयार करने, उसे अपलोड करने आदि में व्यर्थ जाता है। सरकार सभी स्कूल अध्यापकों को कम्पूटर टेबलेट (टैब) देगी ताकि सभी अध्यापक अपने स्कूल के बच्चों का ऑनलाईन रिकार्ड रख सकें। उनकी उपस्थिति, रिजल्ट, स्कॉलरशिप आदि का डाटा तैयार कर सकें और डिपार्टमेंट भेजने के लिए अलग–अलग सूचियां न तैयार करनी पडें। इस टैब का इस्तेमाल टीचर्स की ऑनलाईन ट्रेनिंग और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में भी होगा। अध्यापकों की सुविधा के लिए स्कूलों में मॉर्डन स्टाफरूम बनाने और उसमें कॉफी मशीन इत्यादि लगाने का काम चल रहा है।

56. हम सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासिस शुरू कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर विपरीत परिस्थितिओं में स्वयं को सुरक्षित बनाये रखने का आत्मविश्वास हो और वो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए शारारिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हों। इसके लिए शिक्षा विभाग के बजट में 10 करोड़ रूपये की अलग से व्यवस्था की है।

57. दिल्ली में आज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चो के माता–पिता, बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। जिन परिवारों के बच्चों को अभी एडमिशन लेना है उनके पास स्कूल की पढ़ाई की क्वालिटी, माहौल, सुविधाओं की कोई अधिकारिक सूचना नहीं होती। इसलिए इस साल से दिल्ली सरकार एक नई योजना ला रही है जिसके तहत दिल्ली के हर स्कूल का मूल्यांकन कराया जायेगा उनके बीच पढ़ाई की व्यवस्था और माहौल को लेकर हैल्दी कम्पीटिशन होगा और लोगों के पास स्कूल से संबंधित अधिकारिक सूचनायें होंगी। ताकि स्कूलों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया जा सके। इस मकसद के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से 15 करोड़ रूपया डी.सी.पी.सी.आर. को देने का फैसला किया है।

58. डिफेंस सर्विसिस में युवाओं की रूचि जगाने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कैडेटों को प्रशिक्षण की अवधि में 3 वर्ष के लिए प्रति माह 2000 रुपये की वित्तीय सहायता/प्रशिक्षण भत्ता देने का निर्णय किया है।

59. राष्ट्रीय स्कूल खेलों में दिल्ली इस बार भी शीर्ष पर रहा और उसने इन खेलों में कुल मिलाकर 426 स्वर्ण पदक, 205 रजत और 169 कांस्य पदक जीते। सरकार उदीयमान खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल ढांचे का निर्माण करने के लिए वचनबद्ध है।

60. खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने में खिलाड़ियों की सहायता के लिए वर्ष 2018–19 में 2 नए कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ये हैं –''खेलो और तरक्की करो'' और ''मिशन एक्सिलेंस'' यानि उत्कृष्टता अभियान। ''खेलो और तरक्की करो'' कार्यक्रम के अंतर्गत 14 से 17 वर्ष की आयु समूह के ऐसे खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो राष्ट्रीय रैंकिंग/अलग–अलग खेलों में रेटिंग की दृष्टि से शीर्ष पर हों और उन्होंने दिल्ली का

प्रतिनिधित्व किया हो। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। ''मिशन एक्सिलेंस'' कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी आयु समूह के खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने के वास्ते वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए 2018–19 के बजट में 35 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है ।

61. स्थानीय स्तर पर मोहल्ला एवं कालोनियों में खेलों में जनता को प्रोत्साहित करने एवं भाग लेने के लिए विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में खेल–कूद आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए 2018–19 में 20 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

62. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान–आईआईआईटी के कैम्पस के निर्माण का दूसरा चरण 250 करोड़ रुपये की लागत से पूरे जोर–शोर से जारी है और उम्मीद है कि यह मार्च 2018 तक, यानि इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे आईआईआईटी में दाखिले के लिए सीटों की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 2,500 की जा सकेगी। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टॅडीज का निर्माण कार्य 132.47 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय–डीटीयू का पूर्वी कैम्पस चालू हो गया है, जिसमें 300 सीटें हैं, जिन्हें मिलाकर डीटीयू में सीटों की संख्या, जो 2014–15 में 2,564 थी, वह 2017–18 में बढ़कर 3,689 हो गई। रजोकरी में प्रौद्योगिकी संस्थान और मंगोलपुरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान–आईटीआई 2016–17 में चालू किए गए।

63. कर्मपुरा और लोधी रोड में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दो नए परिसरों ने 2017–18 में काम करना शुरू कर दिया। पिछले तीन वर्षों के दौरान अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दाखिलों की

कुल संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह 2015–16 की 1,757 से बढ़ कर 2017–18 में 2,465 पर पहुंच गई। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्ययन केंद्र ने दो पाठ्यक्रमों : एम.ए. (शिक्षा) और एम.ए. (पूर्व–शैशव शिक्षा) के साथ सितम्बर 2017 को लोधी रोड परिसर में कार्य करना शुरू कर दिया। इस परिसर में 2018–19 के दौरान बी.एड और एम.एड के दो और पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

64. रोहिणी और धीरपुर में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नए कैम्पस का निर्माण कार्य 2018–19 में शुरू करने की योजना है। गुरु गोंविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी कैम्पस का निर्माण अगस्त 2017 में 271 करोड़ रुपये की लागत से सूरजमल विहार में शुरू किया गया है। जीजीएसआईपीयू में सीटों की कुल संख्या 2017–18 में बढ़कर 34,094 हो गई।

65. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए पूर्वी परिसर ने शैक्षिक वर्ष 2017–18 से काम करना शुरू कर दिया। दूसरे चरण के दौरान दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एनएसआईटी के मौजूदा परिसरों का विस्तार करने और सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है।

66. अध्यक्ष जी, मैं यह बात गर्व के साथ साझा करना चाहता हूं, कि विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र जोकि आइटीई, सिंगापुर के सहयोग से शुरू किया गया है, में शत–प्रतिशत प्लेसमेंट यानि नौकरी दिलाने का रिकार्ड निरंतर बनाए रखा है और कौशल विकास कार्यक्रम का मॉडल सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। सरकार ने कौशल मॉडल का अनुकरण करने का निर्णय किया है, जिसके तहत दिल्ली में 25 नए विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका लक्ष्य हर वर्ष करीब 25,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है। मैं वर्ष 2018–19 के दौरान 25 नए विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र खोलने के लिए 315 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र, जौनापुर के निर्माण

के लिए 85 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है जिसकी कुल लागत 254 करोड़ रूपये कैबिनेट द्वारा दिसम्बर 2017 में अनुमोदित की गयी है ।

67. मुझे माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली को नया कारोबार शुरू करने वालों (स्टार्ट–अप्स) का केंद्र बनाने के उद्देश्य से इन्क्यूबेशन केंद्र कारगर ढंग से काम कर रहे हैं। वर्तमान में 76 स्टार्ट–अप्स 11 इन्क्यूबेशन केन्द्रो में काम कर रहें हैं। ये स्टार्ट–अप्स मात्र इंजीनियरी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं हैं, बल्कि सामाजिक विज्ञानों और प्रबंधन के क्षेत्र से भी सम्बद्ध हैं। हमारा प्रयास 5 वर्षों में 500 से अधिक कंपनियां स्थापित करने और विद्यार्थियों को उद्यमी और इनोवेटिव बनाने का है, ताकि वे नौकरी मांगने वालों की बजाए नौकरी देने वाले बन सकें।

68. उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान अनुदान नाम का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसी संस्थान द्वारा बाहरी स्रोतों से जुटाए गए संसाधनों के बराबर यानि मैचिंग ग्रांट दिया जाता है। आईआईआईटी–डी ने इन्फोसिस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। इसकी स्थापना इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा दिए गए 24 करोड़ रुपये के तीन वर्षीय अनुदान कोष से की गई है।

69. उच्चतर शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सात विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों/संस्थानों के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ''योग्यता एवं आर्थिक स्थिति संबंधी वित्तीय सहायता'' नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड रखने वाले विद्यार्थियों को शत प्रतिशत ट्यूशन फीस के समकक्ष वित्तीय सहायता दी

जाती है। जो विद्यार्थी किसी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कवर न किए गए हों, और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो, वे भी ट्यूशन फीस की आधी राशि (50 प्रतिशत) के समान राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। 2.50 लाख रुपये से अधिक लेकिन 6 लाख रुपये तक वार्षिक परिवार आय वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत ट्यूशन फीस के 25 प्रतिशत के समान वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

70. दिल्ली मे 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर शिक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को ऋण सहायता देने के लिए 2016–17 में सरकार ने दिल्ली उच्चतर शिक्षा और कौशल विकास लोन गारंटी कार्यक्रम शुरू किया था। अब इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसके दायरे में अन्य राज्यों/दिल्ली से बाहर, लेकिन भारत में स्थित केंद्रीय संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है।

71. दिल्ली, निस्संदेह, समृद्ध धरोहर और संस्कृति का खजाना है। दिल्ली की धरोहर के संबध में दुनिया भर के रिसर्चर्स को अवगत कराने और उन्हे आगे की रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आर्काइवल रिकार्डस के डिजिटाइजेशन करने और उनकी माइक्रो फिल्म बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह परियोजना सात महीने पहले शुरू की गयी थी और अब तक 20 लाख आर्काइवल रिकार्डस का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने यानि अप्रैल 2018 तक यह सेवा देश और दुनिया के रिसर्चर्स के लिए उपलब्ध हो जायेगी।

72. अध्यक्ष जी, दिल्ली में कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2018–19 में कुछ नए कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है। नए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन

के लिए इस वर्ष बजट में 36 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 13 नई भाषा अकादमियों की स्थापना, एक अंग्रेजी भाषा की अकादमी और राज्य स्तरीय नृत्य एवं गायन प्रतिभा खोज के लिए वार्षिक श्रृंखलाओं का आयोजन, सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन और पुरातत्व एवं अभिलेख में रिसर्च फैलोशिप आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य

73. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर काफी जोर दिया है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव वाले क्षेत्रों और कम मात्रा में सुविधाओं वाले क्षेत्रों, विशेषकर झुग्गी झोंपड़ी बस्तियो, स्लम, अनधिकृत कालोनियों, घनी आबादी वाले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। दिल्ली में 3 स्तरीय स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, पोलिक्लिनिक और अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली के नागरिकों को उनके निवास के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी तक 164 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 80 लाख व्यक्तियों ने मोहल्ला क्लिनिकों में उपचार सेवाओं का लाभ उठाया। मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना के लिए 530 स्थानों का चयन किया गया है और हमारा लक्ष्य 1,000 मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण करने का है। इसी प्रकार 24 पॉलिक्लिनिक काम कर रहे हैं और 94 औषधालयों की पहचान की गई है, जहां ऐसे पॉलिक्लिनिक शुरू किए जाएंगें। इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम किया जा सकेगा।

वर्ष 2018–19 के दौरान मोहल्ला क्लिनिकों और पॉलिक्लिनिकों के लिए मैं 403 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं।

74. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या मौजूदा 10,000 से बढ़ा कर 20,000 पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। अम्बेडकर नगर में 600 बिस्तर का अस्पताल और बुराड़ी में 800 बिस्तर का अस्पताल वर्ष 2018–19 में तैयार हो जाएगा। द्वारका में 1,500 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है। दिल्ली सरकार के सात मौजूदा अस्पतालों में 2,546 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे। मादीपुर, ज्वालाहेड़ी, हस्तसाल, सरिता विहार, दीनदारपुर, केशवपुरम और छतरपुर में नए अस्पतालों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। मैं नए अस्पतालों के निर्माण और दिल्ली सरकार के मौजूदा अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए 450 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूॅं।

75. दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले रोगियों के डॉयगनोस्टिक–टेस्ट निःशुल्क किये जाते हैं। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा रैफर किए जाने पर निर्दिष्ट सूचीबद्ध प्राइवेट केन्द्रों में एमआरआई, सीटी, पीईटीसीटी, रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कलर डोपलर, इको, टीएमटी, ईईजी और ईएमजी जैसी रेडियोलॉजिकल सेवाएं भी सभी रोगियों के लिए निःशुल्क हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2018–19 में 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

76. हमारी सरकार ने दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों, एसिड हमलों के पीड़ितों और थर्मल या तपन से जले घायलों के खर्च की लागत वहन करने का भी निर्णय लिया है, भले ही ऐसे पीड़ित व्यक्ति की आमदनी कितनी ही क्यों न हो और वह कहीं का भी रहने

वाला हो। इसके अलावा, दिल्ली सरकार के 24 अस्पतालों को अधिकृत किया गया है कि वे रोगियों को 48 सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में निशुल्क शल्यचिकित्सा के लिए भेज सकते हैं। दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए 2018–19 में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

77. भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में कोई दुर्घटना होने या अन्य आपात स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए ''प्रथम मददगार वाहन''–फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल (एफआरवी) प्रदान करने के एक प्रायोगिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। प्रशिक्षित ऐम्बूलेंस कार्मिकों द्वारा संचालित 16 मोटरसाइकिलों के साथ यह कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इससे तंग गलियों और भीड़ भरे क्षेत्रों में बचाव कार्रवाई शीध्र संचालित करने में मदद मिलेगी। हमारी कैबिनेट और माननीय उपराज्यपाल इस कार्यक्रम को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं।

78. सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोगी कल्याण समितियां बनायी जाएंगी और प्रत्येक जन स्वास्थ्य केन्द्र जैसे मोहल्ला क्लिनिक, पोलिक्लिनिक और दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों व सीड पीयूएचसी में उसकी उप–समिति के रूप में एक जन स्वास्थ्य समिति गठित की जायेगी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रबंधन में बेहतर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। वर्ष 2018–19 में इस कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी ली जा रही है।

79. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले मोबाइल वैन क्लिनिकों की स्थापना की जाएगी जो विशेष रूप से आंख और कान संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे। वर्ष 2018–19 में इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। दिल्ली कैबिनेट और माननीय उपराज्यपाल ने इस कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है।

80. हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए 'सबके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम' शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2018–19 में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

81. हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवसायियों के कौशल में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा ताकि व्यावसायिक विकास और क्षमता निर्माण किया जा सके। वर्ष 2018–19 में इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

82. मैं वर्ष 2018–19 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6729 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 5741 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 988 करोड़ रुपये पूंजी व्यय से सम्बद्ध हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3,259 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित 3,259 करोड़ रुपये का परिव्यय वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमानों में प्रस्तावित स्वास्थ्य क्षेत्र के 2,152 करोड़ रुपये के परिव्यय से 51.44 प्रतिशत और 2,627 करोड़ रूपये के बजट अनुमानों की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।

<u>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</u>

83. दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्हें मदद पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए ''मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा'', नाम से एक नया कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली के करीब 77,000

वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भेजा जाएगा, जिसका पूरा खर्च बीमा सहित दिल्ली सरकार वहन करेगी। वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 53 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी इसे माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद है कि उपराज्यपाल महोदय दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की इस महत्वपूर्ण योजना को जल्दी ही मंजूरी दे देंगे।

84. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों, विशेष रूप से संकट ग्रस्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और तदनुरूप उनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रही है। हम करीब 7 लाख लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन संकट ग्रस्त महिलाएं, विधवाएं आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 2018–19 में 1,833 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है जबकि 2017–18 के संशोधित अनुमान में यह राशि 1,778 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2016–17 का व्यय 1,091 करोड़ रूपये है।

85. सरकार ने एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (ICDS) के अंतर्गत 10,897 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाओं का स्तर बढ़ाने का निर्णय किया है, जो लगभग 12 लाख बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और स्कूल–पूर्व गतिविधियों से संबद्ध आदि को सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं।

86. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगी, जिससे आईसीडीएस परियोजना के अंतर्गत सेवाओं और कार्यक्रमों की समुचित निगरानी और रिपोर्टिंग करने में मदद मिलेगी। 2018–19

के दौरान ''प्रोत्साहित आंगनवाड़ी उन्नयन कार्यक्रम'' के अंतर्गत विभाग बच्चों के लिए मेज, कुर्सी, चटाईयॉ, खिलौने आदि उपलब्ध कराते हुए मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाएगा। मैं एक नया कार्यक्रम ''अर्ली–चाइल्डहुड–एजुकेशन के बारे में अभिभावकों और आंगनवाड़ी समितियों के लिए प्रशिक्षण'' भी शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इन कार्यक्रमों के लिए 2018–19 में 56 करोड़ रुपये तथा आईसीडीएस के अंतर्गत 541 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

87. हमारी सरकार ने नवंबर, 2017 में 3 हाफ–वे होम शुरू किए, जिनमें नव–किरण–1 व 2, रोहिणी सैक्टर–3 में महिलाओं के लिए तथा नव–चेतना, रोहिणी सेक्टर– 22 में पुरुषों के लिए बनाया गया है। 2018–19 के दौरान 2 और हाफ–वे होम संचालित किए जाएंगे।

88. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित छात्रों के लिए मैं श्लाडली योजनाश के पैटर्न पर 18 वर्ष की आयु तक के छात्रों के नाम पर फिक्स्ड डिपोजिट योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूॅ। उम्मीद है कि गरीब छात्रों के लिए सरकार की इस योजना को आदरणीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी भी मिल जायेगी।

89. अनुसूचित जाति उप–योजना (बजट शीर्ष 789) के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 1,152 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह राशि वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है।

90. हमारी सरकार ने ''जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना'' नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत दिल्ली के स्कूल से कक्षा 10वीं व 12वीं पास या कक्षा 12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्रदान की जाती है ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकें। ऐसे अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को

निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो और यदि परिवार की आय 6 लाख रुपये तक होगी तो सरकार 75 प्रतिशत फीस वहन करेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह स्टाइपंड कोचिंग के दौरान 4 से 5 माह तक दिया जाएगा। वर्ष 2018–19 के लिए मैं इस कार्यक्रम हेतु 24 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूं।

91. हमने एक नया कार्यक्रम ''अल्कोहल और नशीले पदार्थों की रोकथाम'' शुरू करने का निर्णय किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में नशे की लत छुड़ाने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना और इस दिशा में पूरक उपाय करना है। इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित संगठनों की मदद ली जाएगी। इसके लिए वर्ष 2018–19 के लिए 1 करोड़ रूपये की राशि रखी गयी है। आवश्यकता पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना को माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद लागू किया जायेगा।

92. मैं 2018–19 में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 4,155 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं। इसमें से 3,700 करोड़ रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र के तहत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गई है।

जलापूर्ति और सीवर

93. अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड की कार्य निष्पादन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है।

94. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दिल्ली में कितना पानी आता है, सारे पानी का कितना–कितना हिस्सा कौन–कौन सी कालोनी में भेजा जाता है, यह जानने के लिए कहीं भी कोई बल्क वाटर मीटर नहीं लगा है। 70 साल में अब तक हमारे पास यह डेटा तक नहीं है

कि दिल्ली की किस–किस कालोनी में कितना पानी भेजा जाता है, उसमें कितना चोरी होता है और कितना लीक होता है। पिछली बार के आउटकम बजट के रिव्यू में यह बात सामने आयी कि दिल्ली में 47 प्रतिशत पानी, नॉन रिवेन्यू वाटर है। यानि दिल्ली जल बोर्ड को अपने करीब आधे पानी का यही पता नहीं है कि वह लीक हो रहा है या चोरी हो रहा है। पहली बार हमारी सरकार पूरी दिल्ली में बल्क वाटर मीटर लगाने का प्रोजक्ट लेकर आयी है ताकि पता तो चले पानी जा कहां रहा है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सभी प्राईमरी और सैकेंडरी यूजीआर और सभी टैपिंग पर मीटर लगाये जायेंगे। इससे पानी की चोरी पकड़ी जा सकेगी और एक तरह से रोजाना पानी का आर्डिट होगा। इस बल्क वाटर मीटर्स का पूरा डेटा हम वेबसाईट पर डालेंगे ताकि दिल्लीवासियों को भी पता रहे कि उनकी कालोनी में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कितना पानी आ रहा है और वह कहां जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने की पूरी रूपरेखा मैं बजट के अगले भाग में रखूंगा।

95. दिल्ली सरकार सीवेज ट्रीटमेंट की पूरी अवधारणा को बदलने पर काम कर रही है। पहले दिल्ली में बड़े–बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं। इनसे ट्रीट होकर पूरी दिल्ली में लगभग 450 एमजीडी पानी दिल्ली जल बोर्ड के पास उपलब्ध होता है। लेकिन इसमें से केवल 89 एमजीडी पानी ही अभी इस्तेमाल हो रहा है और बाकि का 361 एमजीडी पानी रोजाना यमुना में बहा दिया जाता है। इस पानी को पीने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता लेकिन दिल्ली को हरा–भरा बनाने के लिए सड़कों के किनारे और पार्कों में बागवानी, वर्कशॉप, इंडस्ट्रीयल कूलिगं टॉवरस आदि में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया के कई देश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले एक–एक बूंद पानी का सदुपयोग कर रहें हैं। इससे उन्हे पीने के पानी की बचत भी होती है। लेकिन दिल्ली में हम ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे

हैं क्योंकि हमने बड़े–बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगायें है। अब सरकार पूरी दिल्ली में छोटे–छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगायेगी। जैसे एक कालोनी में छोटा एसटीपी लगाया जायेगा उससे निकलने वाले साफ पानी को वहीं लोगों के घरों में शौच आदि के लिए, उस क्षेत्र में हरियाली के लिए अथवा किसी वाटर बॉडी में इस्तेमाल किया जायेगा। बुराड़ी, छतरपुर, किराड़ी, नरेला, जींदपुर, पल्ला, बवाना, कंझावला, बदरपुर, मुंडका और नजफगढ़ की विभिन्न कालोनियों में ये प्रोजक्टस लगाये जायेगें। इनके पूरे होने की पूरी समय सीमा भी मैं बजट के अगले हिस्से में रखूंगा।

96. सीवर लाइनों की वाहक क्षमता में सुधार के लिए 162 किलोमीटर पेरीफेरियल सीवर लाइन का चयन ट्रेंचलेस टेक्नोलोजी के साथ उन्हें नया रूप देने के लिए किया गया है। इससे पुरानी सीवर लाइनों का जीवनकाल 50 वर्ष तक बढ़ जाएगा।

97. दिल्ली जल बोर्ड ने पालम, बिजवासन, मटियाला, द्वारका, नजफगढ़, मुंडका, रिठाला, विकासपुरी निर्वाचन क्षेत्रों में 162 कालोनियों में चरणबद्ध तरीके से आंतरिक सीवर लाइन बिछाने की योजना बनाई है, जिसे दिसंबर 2020 तक अलग–अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। इन कालोनियों का मल–जल निलोठी, द्वारका, रिठाला और नजफगढ़ मल–जल उपचार संयंत्रों में ले जाया जाएगा और इस कार्यक्रम से करीब 13 लाख की आबादी को लाभ होगा। जहां कहीं मल–जल उपचार संयंत्र का मौजूदा ढांचा विद्यमान नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत मल–जल उपचार संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। प्रारंभ में 7 विकेंद्रीकृत मल–जल उपचार संयंत्र बनाए जाएंगे, जिससे 20 अनाधिकृत कालोनियों और 5 गांव कवर किए जा सकेंगे। यह कार्य जुलाई 2018 में शुरू किया जाएगा और इसे दिसंबर 2019 में पूरा करने का लक्ष्य है।

98. हमारी सरकार ने दिल्ली में सेप्टेज प्रबंधन के नियमन की योजना बनाई है, ताकि निर्दिष्ट स्थानों पर सेप्टेज का समुचित निपटान किया जा सके। इसके लिए ''दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम 2018'' बनाये जायेंगे। ये विनियम आवश्यक अनुमोदनों के बाद दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 का हिस्सा बन जाएंगे।

99. वर्तमान जलापूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए वजीराबाद जल शोधन संयंत्र के कमान क्षेत्र के अंतर्गत 15 किलोमीटर लंबी पुरानी और रिसाव कर रही पाइप लाइनों को बदलने का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। उम्मीद है कि यह काम पूरा होने पर 4 से 5 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की बचत होगी, जिससे मध्यवर्ती और दक्षिणी दिल्ली में पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बेहतर की जा सकेगी। इसके अलावा 2018–19 में 80 किलोमीटर लंबे पुराने वितरण नेटवर्क के बदलने का काम शुरू किया जाएगा।

100. दिल्ली जल बोर्ड ने जलापूर्ति को युक्तिसंगत और समानता पर आधारित बनाने के लिए मायापुरी और सोनिया विहार में भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू किया है। फरवरी 2019 में इन जलाशयों के चालू हो जाने के बाद लगभग 5 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। नजफगढ़ और मुंडका में दो और जलाशयों का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है और दिसंबर 2018 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन दो जलाशयों के चालू हो जाने पर लगभग 80 अनधिकृत कालोनियों और 10 गांवों में फिल्टर किए गए पानी की आपूर्ति की जा सकेगी, इससे करीब 4.5 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। 1,665 अनियमित कालोनियों में से 1,209 कालोनियों में दिसम्बर 2017 तक पाइप जलापूर्ति नेटवर्क का विस्तार किया जा चुका था, जबकि वर्ष 2016–17 तक 1,144 कालोनियों में जलापूर्ति की जा सकी थी। शेष

कालोनियों में पाइप जलापूर्ति नेटवर्क का विस्तार दिसंबर 2018 तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

101. मैं 2018–19 में जलापूर्ति और सीवर के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 2,777.50 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं, जिसमें करीब 4.5 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 20 किलोलीटर निःशुल्क जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 427.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी शामिल है। जलापूर्ति और सीवर के लिए 2018–19 में कुल आवंटन 2017–18 के संशोधित अनुमान की तुलना में 19.85 प्रतिशत अधिक है।

आवास और शहरी विकास

102. अध्यक्ष जी, अनियमित कालोनियों में सड़कों और नालियों का निर्माण, जलापूर्ति, सीवर प्रणाली, स्वच्छता और गलियों में प्रकाश आदि बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। इन कार्यों के लिए मुख्य रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों को धन दिया जा रहा है, जिनमें डीएसआईआईडीसी, आई एंड एफसी और दिल्ली जल बोर्ड शामिल हैं। 2018–19 के दौरान अनियमित कालोनियों में ढांचागत विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 2017–18 के संशोधित अनुमान में इस मद के लिए 840 करोड़ रुपये दिए गए थे। यानि अनियमित कालोनियों में ढांचागत विकास के लिए इस वर्ष राशि लगभग दोगुनी की जा रही है।

103. इसके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018–19 में दिल्ली के सभी बाजारों एवं विपणन स्थानों में विकास कार्य शुरू करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह भी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। आमतौर पर सरकारें बाजार में बैठे लोगों से जीएसटी तो वसूल लेती हैं लेकिन अगर व्यापारी अपने मार्किट एरिया में कोई विकास कार्य कराना चाहें तो उनकी कोई

सुनवायी नहीं होती। इस साल शुरू की जा रही इस योजना के तहत मार्किट समितियों की सलाह पर विकास कार्यों पर यह पैसा खर्च किया जायेगा।

104. अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने हाल ही में 11 दिसंबर, 2017 को दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति अधिसूचित की है। इसका उद्धेश्य झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का उसी भूमि पर इन–सीटू पुनर्वास करना अथवा 5 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए फ्लैटों में पुनर्स्थापन करना है। 2017–18 के दौरान 1,600 जेजे परिवारों को द्वारका और बापरौला में स्थानांतरित किया गया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) संगम पार्क, लाजपत नगर, देवनगर, करोलबाग और भलस्वा जहांगीरपुरी में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के इन–सीटू पुनर्वास की परियोजनाएं शुरू करेगा। इस परियोजना के लिए भी माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद काम शुरू हो जायेगा।

105. डीयूएसआईबी झुग्गी निवासियों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के निरंतर प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में झुग्गी निवासियों के लिए निकटवर्ती सुसंचालित और सुरक्षित शौचालयों के इस्तेमाल की व्यवस्था करना शामिल है। पिछले 3 वर्षों में करीब 16,000 शौचालय सीटों का नवीकरण या निर्माण किया गया। 1 जनवरी, 2018 से इन शौचालय परिसरों को स्लम निवासियों के लिए निःशुल्क दिन–रात इस्तेमाल हेतु उपलब्ध कराया गया है।

106. मैं विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आवास और शहरी विकास को 2018–19 में 3106 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं जो 2017–18 के संशोधित अनुमान 1812 करोड़ रुपये की तुलना में 71 प्रतिशत अधिक है।

सड़क एवं अन्य आधारभूत ढांचा

107. मान्यवर, बाहरी रिंग रोड पर विकासपुरी से वज़ीराबाद तक एलेवेटेड कोरिडोर को सिग्नल मुक्त किया जा चुका है। इससे विकासपुरी से वज़ीराबाद तक यात्रा समय में लगभग 45 मिनट की बचत होगी।

108. बारापूला नाला–चरण 2 का निर्माण कार्य मार्च 2018 तक पूरा होने की आशा है। इससे रिंग रोड पर वाहनों की भीड–भाड़ से निजात मिलेगी और यात्रा समय में 15 से 20 मिनट की बचत होगी। सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापूला नाला–चरण 3 के एलेवेटेड रोड का निर्माण कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना पर 1260 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह एलेवेटेड रोड बनने से यात्रा समय में 10–12 मिनट कम लगेंगे जबकि अभी इसमें आधा घंटा लगता है। ककरोला मोड़ से वजीराबाद तक नजफगढ़ नाले के साथ–साथ एलेवेटेड रोड का निर्माण कार्य 2018–19 के दौरान शुरु कर दिया जाएगा। इसका निर्माण ग्रेड रोड पर नजफगढ़ नाले के साथ–साथ 25 किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा।

109. बाहरी रिंग रोड पर मुनिरका से आर्मी अस्पताल तक सिंगल फ्लाई ओवर और भीतरी रोड पर जंक्शन बीजे मार्ग पर अंडर पास का निर्माण कार्य जून 2018 तक पूरा होने की आशा है। इस परियोजना के पूरा होने से मुनिरिका और आर्मी अस्पताल के बीच यात्रा समय में 20 मिनट तक की कमी आएगी।

110. आईटीपीओ से भैरों रोड–रिंग रोड जंक्शन से पुराना किला रोड के नीचे 700 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद इंडिया गेट से रिंग रोड पहुंचना आसान हो जाएगा और यात्रा समय में 10–15 मिनट तक की कमी आएगी।

111. 450 करोड़ रुपये की लागत से करावलनगर, भजनपुरा जंक्शन पर फ्लाईओवर तथा गगन सिनेमा, नंदनगरी टी–जंक्शन पर फ्लाईओवर और मंगल पांडेय मार्ग के लोनी रोड पर 6.5 किलोमीटर लंबे अंडरपास का निर्माण कार्य वर्ष 2018–2019 में शुरु कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद य़ात्रा समय में 40 मिनट तक की कमी आएगी। यमुना और आगरा नहर के साथ–साथ डीएनडी फ्लाईओवर और फरीदाबाद के बीच कालिंदी बाईपास का निर्माण कार्य भी 2018–19 में शुरु कर दिया जाएगा।

112. सिग्नेचर ब्रिज से कालिंदी कुंज बाई पास तक एलेवेटेड रोड का निर्माण कार्य भी 2018–19 में शुरु हो जाएगा। इससे वजीराबाद और डीएनडी फ्लाईओवर के बीच रिंगरोड पर यातायात कम होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा समय में 20–30 मिनट की कमी आएगी।

113. हम दिल्ली में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्व हैं। वाई–फाई सुविधा को जल्दी उपलब्ध कराने के लिए यह प्रोजेक्ट आईटी विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग को सौपा गया है। मै वाई–फाई योजना के लिए 100 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हॅूं।

114. मैं 2018–19 में सड़क, सार्वजनिक परिवहन एवं अन्य आधारभूत ढांचे के लिए 5145 करोड़ रुपये के कुल खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 3,080 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 2065 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। इसमें से 2,568 करोड़ रुपये परिवहन क्षेत्र की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किये गये हैं।

विकास

115. मान्यवर, दिल्ली के सभी गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय विधायक अपनी ग्राम विकास परियोजनाओं की स्थिति के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए एनआईसी की सहायता से एक एप्प विकसित किया जाएगा।

116. हमारी सरकार दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में हाईटेक डेमोन्स्ट्रेशन फार्मों के विकास के लिए एक नई योजना–**स्मार्ट कृषि योजना** लागू करेगी। इनसे किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित की गई नई तकनीकों और फसलों की किस्मों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं 2018–19 में इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। दिल्ली में कृषि और बागवानी के चहुंमुखी विकास के लिए एक कृषि नीति बनाई जाएगी।

117. मृदा जांच प्रयोगशाला को अपग्रेड किया गया है। पहले मिट्टी के नमूनों की जांच केवल तीन मान दंडों के आधार पर की जाती थी, दिल्ली के किसानों के फायदे के लिए अब यह जांच 12 मानदंडों के आधार पर की जाती है ।

118. आजादपुर मंडी भारत की सबसे बड़ी मंडी है जहां प्रति वर्ष ताजा फलों और सब्जियों का सर्वाधिक कारोबार किया जाता है। सरकार दिल्ली की सभी मंडियों विशेष कर आजादपुर मंडी के लिए ई–मंडी परियोजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि कारोबार में पारदर्शिता, किसानों को फसल की बेहतर कीमत और किसानो ंको जल्द भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह देश में इस प्रकार का सबसे बड़ा प्रयास होगा क्योंकि अब तक कोई भी

राज्य शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए इस पैमाने पर ई–मंडी की व्यवस्था नहीं कर पाया है।

119. मैं 2018–19 में ग्रामीण विकास और बाढ़ सिंचाई पर 694 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 364 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 330 करोड़ रुपये का पूंजीगत बजट शामिल है। ग्रामीण विकास और बाढ़ सिंचाई क्षेत्र की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 345 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

120. मैं अब अपने भाषण का भाग "ख" प्रस्तुत करता हूॅं।

[भाग–ख]

121. माननीय अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2017 में वस्तु और सेवा कर–जीएसटी लागू होने के बाद से जीएसटी, सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। चालू वित वर्ष में फरवरी 2018 माह तक हमने लगभग 22,887 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह किया जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 17.6 प्रतिशत अधिक है। अनुमान है कि हम चालू वित वर्ष में 26,000 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे।

122. जीएसटी पंजीकरण के तहत विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि निरीक्षकों की फील्ड जॉच के बिना ही डीलरों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र सीधे जारी कर दिये जायें। यह जॉच बाद में की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि डीलरो को उनके पंजीकरण प्रमाण–पत्र तुरंत मिल सकें।

123. विभाग अपने मौजूदा डीलरों में से 75 प्रतिशत को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने में सफल रहा है। लगभग 2.25 लाख नये पंजीकरणों को भी मंजूरी दी गई है। जीएसटी लागू होने से पहले कारोबारियों/बाज़ार संगठनों के साथ 50 परस्पर–संपर्क बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में लगभग 6,700 कारोबारियों ने भाग लिया। प्रमुख बाज़ारों में व्यापारी जागरुकता बैठकें आयोजित की गईं जिनमें व्यापार संघों ने भाग लिया।

124. जीएसटी के बारे में कारोबारियों और बाजार संघों की शिकायतों के समाधान के लिए व्यापारियों के साथ समन्वय और बेहतर संवाद के लिए प्रमुख बाजार क्षेत्रों में जीएसटी सहायता समितियां बनाई गईं हैं। इन सहायता समितियों ने कारोबारी समुदाय की उचित और विशेष शिकायतों के निवारण में विभाग और व्यापारियों में सेतु की तरह काम किया है।

125. अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्ष 2017–18 के लिए 4,700 करोड़ रुपये के उत्पाद राजस्व का लक्ष्य रखा था। फरवरी 2018 तक 4,016 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क के रुप में प्राप्त किये गये, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है।

126. दिल्ली में शराब की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निरंतर खुफिया जानकारी रखी जा रही है। उसी के अनुसार उत्पाद अधिनियम के समुचित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने सहित उचित कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2017–18 में आबकारी विभाग के दस्तों ने 854 गिरफ्तारियां की और 851 एफआईआर करायी। करीब 3.15 लाख बोतल अवैध शराब जब्त की है। आबकारी विभाग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि दिल्ली में शराब के सेवन पर नियंत्रण, निगरानी और नियमन के अपने बड़े लक्ष्य और अधिकृत शराब की उपलब्धता के बीच सूक्ष्म संतुलन बनाए रखें।

[भाग–ग]

127. महोदय, इस साल के बजट से मैं एक और भाग इसमें जोड़ रहा हूं। यह है टाईम–लाईन बजट। यह बजट का भाग 'ग' होगा। इसमें हम बजट में घोषित की गयी कई योजनाओं को पूरा करने की समय सीमा सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय ही रखेंगे।

128. जैसा कि मैंने ग्रीन बजट प्रस्तावों में बताया कि सरकार ने 1000 ई बसें दिल्ली में लाने का फैसला किया है। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी टाईम–लाईन सरकार ने तैयार कर ली है। कंसल्टेंट अपाइंट करने से लेकर बिल्डिंग और फिर बसों की आपूर्ति तक में किस–किस काम में कितना–कितना समय लगेगा इसकी पूरी जानकारी तारीख सहित मेरे बजट भाषण के साथ संलग्न है। इसके लिए 1 जून 2018 तक कंसलटेंट का अपाइंटमेंट हो जायेगा, 31 अगस्त 2018 तक निविदायें मंगा ली जायेंगी। 25 सितम्बर तक निविदायें खोल ली जायेगी। 15 नवम्बर तक कंपनियों का चयन कर उन्हे पत्र जारी कर दिया जायेगा और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में अगले मार्च यानि मार्च 2019 से सड़कों पर ई–बसें चलने लगेंगी।

129. 1000 नई डीटीसी बसें खरीदने की समय सीमा भी सरकार ने तैयार कर ली है। 11 मई तक इसके बिड्स जमा करा लिये जायेंगे। उसके बाद बिड खोलना, फाइनेशियल बिड आदि की प्रक्रिया पूरी करते हुए 20 जुलाई तक वर्क–ऑडर जारी कर दिये जायेंगे। 20 नवम्बर तक 40 बसों की पहली खेप आ जायेगी और इसके बाद 120 बस प्रतिमाह के आधार पर अगले 8 महीने में 960 बसें दिल्ली की सड़कों पर आ जायेगी।

130. इसी तरह 1000 नई कलस्टर बसें भी जोड़ने की समय सीमा भी सरकार ने तैयार कर ली है। इसकी टेक्नीकल बिड्स अभी जमा हो रही हैं। 6 अप्रैल तक फाइनेनशियल बिडस खोल

ली जायेंगी और 30 अप्रैल तक केबिनेट से मंजूरी लेकर 31 मई तक लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया जायेगा। सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 के बीच अलग–अलग सैक्टर्स में 251 बसें और उसके बाद दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 के बीच बाकी 749 बसें दिल्ली की सड़कों पर आ जायेंगी।

131. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट – मैंने पहले स्थानीय स्तर पर छोटे–छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना का जिक्र किया था। सरकार ने इसकी समय सीमा पर भी काम कर लिया है। बुराड़ी क्षेत्र में 20 एमएलडी का एसटीपी दिसम्बर 2019 तक तैयार हो जायेगा। इसी तरह छतरपुर में 22 एमएलडी का एसटीपी 31 मार्च 2020 तक तैयार हो जायेगा। किराड़ी क्षेत्र में 93 एमएलडी का एसटीपी और नरेला, जींदपुर, पल्ला में 115 एमएलडी का एसटीपी 31 मार्च 2020 तक तैयार होगें। बदरपुर, नजफगढ़, कंझावला और मुडंका में भी एसटीपी 31 मार्च 2020 तक तैयार होंगे। इन सब प्लांटस के लिए जमीन चिन्हित करने का काम 31 जुलाई 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा। इनकी टेंडर प्रक्रिया 30 नवम्बर 2018 तक पूरी कर ली जायेगी।

132. मैंने पानी प्रबंधन की बात करते हुए पूरी दिल्ली में बल्क वाटर मीटर लगाने की अति महत्वपूर्ण योजना का जिक्र किया था। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा तैयार टाईमलाईन के अनुसार इस पर काम चल रहा है और यह दिसम्बर 2018 तक पूरा हो जायेगा।

133. मैंने जिक्र किया था कि सरकार सभी दिल्लीवासियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सल हैल्थ केयर स्कीम लेकर आ रही है। सरकार द्वारा तैयार टाईमलाईन के मुताबिक 30 अप्रैल 2018 तक इसकी आरएफपी फाईनल कर ली जायेगी और 15 अगस्त 2018 तक बिड्स प्रोसेसिंग पूरी हो जायेगी। 15 सितम्बर 2018 तक कांट्रेक्ट अवार्ड कर दिया जायेगा। 1 दिसम्बर 2018 से यह योजना लागू कर दी जायेगी।

134. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजक्ट मोहल्ला क्लीनिक बनाने की भी समय सीमा तय कर ली गयी है। 530 मोहल्ला क्लीनिक तथा 230 स्कूलों में स्कूल क्लीनिक बनाने का काम 30 अक्तूबर 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद अगले 4 महीनों में इसमें स्टाफ की नियुक्ति कर सभी मोहल्ला क्लीनिक्स को चालू कर दिया जायेगा।

135. स्वास्थ्य क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण योजना हास्पिटल इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानि एचआईएमएस बनाने की है। एचआईएमएस लागू करने के लिए आरएफपी 30 जून 2018 तक जारी कर दी जायेगी। इसका टेंडर 30 सितम्बर 2018 तक अवार्ड कर दिया जायेगा। पूरी दिल्ली के लिए साफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के काम में करीब 6 महीने लगेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग, ट्रायल, हार्डवेयर परचेज आदि पूरा कर इस योजना को 1 जुलाई 2019 से लागू किया जायेगा।

136. विभिन्न सरकारी सेवाओं की डोर–स्टेप–डिलीवरी, जो कि सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है जिससे दिल्ली में अलग–अलग कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने वाली आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, इसकी भी समय सीमा तय कर ली गयी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर ली गयी है और सरकार द्वारा तैयार समय सीमा के मुताबिक 23 मार्च 2018 यानि कल ही टेंडर खोल लिये जायेंगे। इसके बाद जांच, टेक्नीकल बिंडिग व फाईनेसियल बिड आदि का काम अप्रैल माह में पूरा कर 1 मई 2018 तक चयनित कम्पनी के साथ एर्ग्रीमेंट साईन कर लिया जायेगा और 15 जून 2018 से यह योजना लागू हो जायेगी।

137. सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की परियोजना पर काम चल रहा है। इसका टेंडर 15 जून, 2018 तक अवार्ड कर दिया जायेगा। परियोजना कार्य 15 जुलाई 2018 को शुरू होने और जनवरी 2019 के अंत तक पूरा हो जाने का अनुमान है। इससे पूर्व, इस परियोजना का

7 अप्रैल 2018 तक प्रारंभिक अनुमान जमा करने तथा 22 मई 2018 तक प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी प्रदान करने की संभावना है।

138. गरीबों को राशन देने की योजना देश में काफी लोकप्रिय है। लेकिन इसके बारे में कड़वा सच यह भी है कि इसका एक बड़ा हिस्सा चोरी चला जाता है। दिल्ली सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए गरीब लोगों को दिया जाने वाला राशन सीधे उनके घर पहुंचाने की योजना लेकर आ रही है। डोर–स्टेप–डिलीवरी–ऑफ–राशन नाम की इस योजना से गरीब लोगों के राशन की चोरी रूकेगी, उनको फायदा होगा। इस योजना का विरोध भी हो रहा है। राशन चोरी में लगे लोग, चाहे वो डीलर हों या इस धांधली में शामिल अफसर, इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके लागू होते ही राशन की चोरी पूरी तरह रूक जायेगी और गरीबी दूर करने में कामयाबी मिलेगी। अभी यह योजना माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास लंबित है। जैसे ही माननीय उपराज्यपाल महोदय से इसकी मंजूरी मिलेगी, 21 दिन के अंदर इसका कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया जायेगा। और उसके 30 दिन के अंदर आरएफपी तैयार कर अगले एक महीने में इसकी टेंडर जारी कर दिये जायेंगे। और फिर आरएफपी में तय समय–सीमा में यह लागू कर दी जायेगी।

139. उपरोक्त सभी योजनाओं की टाईमलाईन, बजट भाषण के अंत में संलग्न है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में विचार के लिए बजट प्रस्तुत करता हूँ।

Annexure

TRANSPORT DEPARTMENT

Timelines of Electric Buses

S. No.	Activity	Time-line
1.	Approval of Council of Ministers to engage/procure 1000 low floor electric buses through cluster scheme/DTC	By 30th April, 2018
2.	Appointment of Consultant	By 1st June, 2018
3.	Drafting of specification and tender document	By 30th June, 2018
4.	Approval of Council of Ministers for specification and tender document containing the concessional model including incentive, if any.	By 15th July, 2018
5.	Receipt of bids after floating of tenders	By 31st August, 2018
6.	Evaluation of technical submission	By 20th September, 2018
7.	Opening of price bids	By 25th September, 2018
8.	Approval of Council of Ministers for financial implications to Government towards subsidy	By 31st October, 2018
9.	Issue of Letter of Indent (LoA) and signing of Concession Agreement (s)	By 15th November, 2018
10.	Financial closure of each project	By 28th February, 2019
11.	Supply of buses by the manufacturers to Concessionaire(s)	From 31st March, 2019 onwards, subject to capacity and production of electric buses.

TRANSPORT DEPARTMENT

TIMELINE SCHEDULE FOR 1000 STANDARD CNG BUSES -DTC

	Activity	Timelines
1.	Approval of DTC Board for floating of RFP	08-03-2018
2.	Floating of Tender and Publication of NIT in Newspapers	15-03-2018
3.	Pre-bid meeting	22-03-2018
4.	Issuing of Addendum/Freezing of Bid Document	12-04-2018
5.	Last Date of submission of Bids	11-05-2018
6.	Opening and Evaluation of Technical Bids, seeking clarification from the Bidders, if any, and determination of Responsive |Bidders	08-06-2018
7.	Opening of Financial Bids, Evaluation, and justification for the acceptance of L 1 rates	29-06-2018
8.	Obtaining Approval of DTC Board of L1 rates	13-07-2018
9.	LOI + Work Order	20-07-2018
10.	Prototype Approval	20-10-2018
11.	Arrival of 40 Buses	20-11-2018
12.	Arrival of 120 Buses per month over a period of 8 months, that is total 960 buses	20-12-2018 to 20-07-2019

TRANSPORT DEPARTMENT

Timelines of 1000 Cluster Buses

Sr. No.	Description				Date
A	**CURRENT STATUS**				
1	Tender Opening Date for Cluster No. 13, 14 (Part), 16A & 16B on e-procurement portal of Govt. of NCT of Delhi				21.02.2018
2	Technical Submissions by Bidders				Under evaluation by DIMTS
3	Target date of submission of Technical Evaluation Report by DIMTS to DoT				26.03.2018
B	**ACTIVITY-WISE TIMELINE**				
1	Opening of Price Bid by DoT				By 06.04.2018
2	Submission of Financial Evaluation Report by DIMTS to DoT				By 16.04.2018
3	Approval of Cabinet (to be obtained by DoT)				By 30.04.2018
4	Issue of LOA & Signing of Concession Agreement (Action by DoT)				By 31.05.2018
5	Financial Closure of each project				30.08.2018
6	Induction Schedule of Cluster Buses				
	Sr. No.	**Cluster No.**	**Total Buses**	**Number of Buses**	
				September, 2018 to November, 2018 @ 25% of total buses	**December, 2018 to February, 2019 @ 75% of total buses**
	1	13	350	88	262
	2	14 (Part)	120	30	90
	3	16A	250	63	187
	4	16B	280	70	210
			1000	**251**	**749**

DELHI JAL BOARD / UD

Sewage Treatment Plants:

Name of Scheme	Capacity of STPs (in MLD)	Length of Sewerage network (in Km.)	Present Status	Land Identification & Preparation of estimate	Invitation of Tenders and award of work	Expected date of completion
A	B	C	D	E	F	G
1. Decentralization of STPs & Sewarage system in Burari area	20.5	86	Tenders invited due on 23/04/2018	Identified and informed to DM (North)	31/07/2018	31/12/2019
2. Decentralization of STPs & Sewarage system in Chattarpur area	22.5	147	Land is being identified	Identified and being finalized	31/08/2018	31/03/2020
3. Decentralization of STPs & Sewarage system in Kirari area	93	423	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020
4. Decentralization of STPs & Sewarage system in Narela, Zindpur and Palla area	115	350	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020
5. Decentralization of STPs & Sewarage system in Bawana and Kanjhawala area	203	670	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020

6. Decentralization of STPs & Sewarage system in Badarpur area	45	234	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020
7. Decentralization of STPs & Sewarage system in Mundka (Part) area	15	25	Land is being identified	31/07/2018	30/11/2018	31/03/2020
8. 9+5 STPs in Najafgarh Area (Capacity of the STPs shall be finalized after actual flow measurements in the command area)	177	780	Land under acquisition	Work of STPs already awarded. Estimate for internal sewer lines will be finalized by 31/07/2018	For internal Network by 30/11/2018	31/12/2020

DELHI JAL BOARD

Installation of Bulk Flow Meters:

Project Details	Location	Present Status	Target Date
A	**B**	**C**	**D**
1. SITC of electromagnetic flow meters and GPS system and inlet RTU for various Rising Mains across Delhi including 5 years Operation & Maintenance (86 Nos. Flow meters)	Inlet and Tapings of Primary UGRs	Letter of Indent issued on 21/02/2018	November, 2018
2. SITC of electromagnetic flow meters to be installed at various UGRs/tapings across rising mains of Delhi Jal Board including 5 years Operation & Maintenance (39 Nos. Flow Meters)	Outlet and Tapings of Primary UGRs	It is being re-invited due to higher rates	December, 2018
3. SITC of electromagnetic flow meters at various UGRs/tapings risings mains and outlet of secondary UGRs of Delhi Jal Board for secondary audit including 5 years Operation & Maintenance (2746 Nos. Flow Meters)	For Secondary audit i.e. Inlet, Outlet and Tapings of secondary UGRs	NIT opened on 07/02/2018. Technical evaluation is being done	December, 2018
4. Supply, Installation, Testing and Commissioning of 120 Nos. Electromagnetic flow meters	Inlet and Tapings of Primary UGRs of Chandrawal and Wazirabad WTPs command area	Detailed estimate and NIT is under preparation	December, 2018
5. Supply, Installation and Commissioning of 13 Nos. Electromagnetic flow meters and GPS system for West Delhi, Rohini and RWS Water mains with 05 years O&M	Inlet and Tapings of Primary UGRs of Haiderpur WTP Ph-II	Work Completed, O&M in progress	-

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

Implementation of Universal Healthcare in Delhi:

Milestone	Time-Line
A	B
1. Finalization of RFP	30/04/2018
2. Floating of RFP	15/05/2018
3. Last date of receiving bids	30/06/2018
4. Processing of bids	15/08/2018
5. Award of Contracts	15/09/2018
6. Implementation of Scheme	01/12/2018

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

Aam Aadhmi Mohalla Clinic:

Sl. No.	Milestone	Time-Line	Status	Nature of Activities Parallel/ Sequential
	A	B	C	D
1.	Identification of sites	Nil	Already Identified	Sequential
2.	Allotment of Sites/Permission from Land Owning agencies (**530 sites)**	Nil	Permission granted	Sequential
3.	Joint Survey by PWD and CDMOs	30/4/2018	Started	Sequential
4.	Construction by PWD	Six Months (Being a semi permanent structure) after Joint Survey approval i.e. 31/10/2018	Yet to start	Sequential
5.	Provision of Water & Power	By 30/10/2018	Yet to start	Parallel
6.	Procurement of Equipment and Medicines	Nil	Procurement through contract of CPA under DGHS	Parallel
7.	Requirement of Manpower	Four Months from Activity No.4 completion	Yet to start	Parallel

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

Implementation of Hospital Information Management System:

Sl. No.	Milestone	Time-Line	Status	Nature of Activities Parallel/ Sequential
	A	B	C	D
1.	Finalization of Tender Document through IT Department	15/05/2018	Under Process	Sequential
2.	Requisite vetting by concerned Departments	15/06/2018	Yet to start	Sequential
3.	Floating of RFP	30/06/2018	Yet to start	Sequential
4.	Last date of receiving bids	15/08/2018	Yet to start	Sequential
5.	Award of Tender	30/09/2018	Yet to start	Sequential
6.	Development of software	6 months i.e. 01/10/2018 to 31/03/2019	Yet to start	Sequential
7.	Training of Staff in batches of 40	2 months i.e. 01/04/2019 to 31/05/2019	Yet to start	Sequential
8.	Completion of Field Trial	1 month i.e. 01/06/2019 to 30/6/2019	Yet to start	Sequential
9.	Formal Launch of HIMS	01/07/2019	Yet to start	Sequential
10.	Procurement of Hardware (Computers, Printers, Scanners, Lease Line) etc. after award of tender will be initiated simultaneously.	3 months i.e. 01/10/2018 to 31/12/2018	Yet to start	Parallel

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Implementation of Scheme – Doorstep Delivery of Public Services:

	Milestone	Time-Line
	A	B
1.	Floating of eTender	01.03.2018 (with effect from 02.03.2018)
2.	Pre-Bid Meeting	08.03.2018 (Concluded)
3.	Response to queries	14.03.2018
4.	Last date of submission of bid	23.03.2018 upto 02.00pm
5.	**Opening of eTender**	**23.03.2018 at 03.00pm**
6.	Scrutiny of documents submitted in relation to Pre-qualification	03.04.2018 (05 Working days) - Depends on number of bids and their reply to various queries sought by the Committee.
7.	Presentation on the Project	06.04.2018 (03 days notice to bidder)
8.	Opening of Technical bid	10.04.2018 (one working day)
9.	Scrutiny of documents submitted in relation to Technical-qualification and awarding marks by the Committee	17.04.2018 (05 Working days) - Depends on number of bids and their reply to various queries sought by the Committee before awarding the marks.
10.	Opening of Financial bid and recommending the successful bidder by the Committee	19.04.2018
11.	Approval of recommendations of the Committee by the Hon'ble Minister	20.04.2018
12.	Approval by the Finance Department	25.04.2018
13.	Vetting of the draft agreement by the Law Department	27.04.2018
14.	**Signing of agreement with the successful bidder**	**01.05.2018**
15.	**Launching of project**	**15.06.2018 (T+6 weeks as per RFP**

EDUCATION DEPARTMENT

CCTV Cameras in Schools by PWD:

Sl. No.	Milestone	Time-Line
	A	B
1.	Submission of Preliminary Estimates	07/04/2018
2.	Issue of A/A & E/S	22/05/2018
3.	Award of Work	15/06/2018
4.	Start of Work	15/07/2018
5.	Completion of Work	15/01/2019

FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT

Implementation of scheme on Doorstep Delivery of Ration:

Sl.No.	Milestone	Time-Line
	A	B
1.	Obtaining consents of beneficiaries for whole wheat atta through FPS in atleast one cycle of distribution of foodgrains	30 days
2.	Compilation of the consents by the Department	07 days
3.	Finalization of terms of reference for appointment of consultants and its approval from Finance Department (Parallel to the process of obtaining consents)	10 days
4.	NIT for appointment of consultant	21 days
5.	Process of finalization of bid from the Finance Department (Parallel to the process of obtaining consent)	10 days
6.	Preparation of RFP by the consultant	30 days
7.	Vetting of RFP from Finance, Law, Food Safety, IT and Planning Department	15 days
8.	Tender for appointment of service provider (Pre-bid conference after 10 days)	21 days
9.	Processing of bids, approval of Departments and award of work	15 days
10.	Amendment to the Delhi Specified Control Order, 1981	Parallel to the consent and tender process
11.	Time required by the Service provider for delivery of service on the doorstep, which need engagement of transporters, setting up of godown/storage facility, milling & packaging unit and engagement of manpower	Time Line as provided in RFP by the consulant